

द बगि पकिचर/वशेष : मशिन स्मार्ट सटि

संदर्भ व पृष्ठभूमि

हाल ही में स्मार्ट सटि परयोजना में शहरों की चयन प्रक्रिया के चौथे और अंतिम चरण में 9 और शहरों को शामिल किया गया। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 15 शहरों के बीच प्रतियोगिता कराई थी, जिनमें से इन शहरों का चयन किया गया। वदिति हो कस्मार्ट सटि परयोजना में 90 शहरों का चयन पहले ही हो चुका है।

- गाँवों से शहरों की ओर नरितर हो रहे पलायन के चलते भारतीय शहरों पर बोझ बराबर बढ़ता जा रहा है। भारत की जनसंख्या का 31 प्रतशित हसिसा शहरी है और और जीडीपी में इसका योगदान 63 प्रतशित है।
- वर्ष 2030 तक जनसंख्या का 40 प्रतशित हसिसा शहरी हो जाएगा और तब देश की जीडीपी में इसका योगदान लगभग 75 प्रतशित हो जाएगा, ऐसे में शहरों में नागरिक सुवधियों को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी।
- देश में फलिहाल 4041 शहरों तथा कस्बों में स्थानीय नकिया हैं और इनमें लगातार बढ़ती आबादी के मद्देनज़र सामाजिक, आर्थिक और बुनयादी ढाँचे के विकास की आवश्यकता है।

स्मार्ट सटि की परभाषा

- स्मार्ट सटि की ऐसी कोई परभाषा नहीं है जसि सर्वत्र स्वीकार किया जाता है।
- अलग-अलग लोगों के लिये इसका आशय अलग-अलग होता है।
- स्मार्ट सटि की संकल्पना, शहर-दर-शहर और देश-दर-देश भिन्न होती है।
- स्मार्ट सटि का भारत में अलग अर्थ होगा हेतु कुछ पारभाषिकी सीमाएँ अपेक्षित हैं।
- भारत में कसि भी शहर नवासी की कल्पना में, स्मार्ट शहर तस्वीर में ऐसी अवसंरचना एवं सेवाओं की अभीष्ट सूची होती है जो उसकी आकांक्षा के स्तर को वर्णित करती है।
- नागरिकों की आकांक्षाओं और ज़रूरतों को पूरा करने के लिये, शहरी योजनाकार को लक्ष्य आदर्श तौर पर पूरे शहरी पारस्थितिकी तंत्र का इस प्रकार विकास करना होता है।
- यह व्यापक विकास के चार स्तंभों--संस्थागत, भौतिक, सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना में दिखाई देता है।
- यह दीर्घावधिक लक्ष्य हो सकता है और चुने हुए शहर 'स्मार्टनेस' की परतें जोड़ते हुए संवर्धित रूप से ऐसी व्यापक अवसंरचना तैयार करने की दशा में कार्य कर सकते हैं।

(टीम दृष्टि इनपुट)

स्मार्ट सटि चयन का आधार

- संकल्पना और विकास के वभिन्न स्तर
- परिवर्तन और सुधार की इच्छा
- शहर के नवासियों के संसाधन
- लोगों की आकांक्षाओं का स्तर
- हालिया चरण में कुल 10 नए शहर शामिल

इस चरण में उत्तर प्रदेश के तीन शहरों-बरेली, मुरादाबाद और सहारनपुर के अलावा तमलिनाडु में इरोड, दादरा नगर हवेली में सलिवासा, लक्षद्वीप में कावारती, अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर और दमन दीव में दीव को जगह मली है।

- इस चरण में स्मार्ट सटी परियोजना के मानकों पर खरे उतरने वाले चयनित शहरों में सलिवासा पहले स्थान पर रहा ।
- एक शहर का चयन पूर्वोत्तर राज्य से किया गया है, लेकिन संबद्ध राज्य में वधिनसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लागू हो जाने के कारण मेघालय की राजधानी शिलांग का नाम अभी घोषित नहीं किया गया है ।
- चयनित शहरों ने अपने स्मार्ट सटी प्रस्तावों में परियोजना के मानकों के अनुरूप 12,824 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की कार्ययोजना पेश की है । इस राशि से इन शहरों में जीवन को सुवधिपूर्ण और सुगम बनाया जा सकेगा ।
- इन 9 नई स्मार्ट सटी में 10 हजार 629 करोड़ रुपए क्षेत्र आधारित विकास पर खर्च होंगे, जबकि 2,185 करोड़ रुपए पैन सटी परियोजनाओं पर खर्च होंगे । इससे 35.3 लाख लोग लाभान्वित होंगे ।
- इसके तहत इन शहरों में स्मार्ट रोड, नदी-तालाबों को पुनर्जीवित करना, साइकलिंग ट्रैक, वॉक पाथ, स्मार्ट क्लासरूम, कौशल विकास केंद्र, स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन, सूचना तकनीक आधारित म्युनिसिपल सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी ।
- इस चरण में वजिता शहरों ने अपने स्मार्ट सटी के प्रस्तावों की गुणवत्ता में 19 प्रतिशत (औसत) चयन की पात्रता के लिये सुधार किया ।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार इस परियोजना के पहले चरण में 100 शहरों में प्रत्येक को 500 करोड़ रुपये दे रही है । शेष राशि संबद्ध शहर स्थानीय निकाय बांड के अलावा नजि और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी से जुटा रहे हैं । देशभर में कुल 100 स्मार्ट सटी पर 2 लाख 3 हजार 979 करोड़ रुपए का निवेश होने की संभावना है ।

विकास के लिये विशेष कंपनी (Special Purpose Vehicle-SPV)

स्मार्ट सटी परियोजना के लिये वकिसति की जाने वाली भूमि और इसके क्रयान्वयन का विशेष अधिकार **एसपीवी** के पास है । इस कंपनी का काम शहर के विकास में शामिल सभी एजेंसियों और स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व के बीच तालमेल सुनिश्चित करना है । मशिन स्मार्ट सटी के लिये एसपीवी को कंपनी कानून के तहत बनाया गया है ताकि पेशेवर क्षमता और जवाबदेही को सबसे अच्छे ढंग से सुनिश्चित किया जा सके । इस मशिन में नजि भागीदारी के लिये महानगरों की बड़ी सलाहकार संस्थाओं और कंपनियों पर निर्भर रहने के बजाय स्थानीय कंपनियों और तकनीकी संस्थाओं के साथ साझेदारी की संभावनाएँ तलाशी जानी चाहिये ।

इसके लिये शहरी स्थानीय निकायों की क्षमताओं का निर्माण करने और उपलब्ध संसाधनों को वकिसति करने की आवश्यकता है । इस तरह की व्यवस्था से सस्ते नवाचार की भावना भी झलकती है जैसे स्मार्ट सटी मशिन के दशा-नरिदेशों में बढ़ावा दिया गया है ।

स्मार्ट सटी योजना में दो तरह की परियोजनाएँ बन रही हैं--1. शहरी बुनियादी ढाँचे से संबंधित 2. सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीक से । पुराने शहर में बुनियादी ढाँचे के विकास में समय लगने की संभावना है और ऐसे में सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीक से जुड़ी सुविधाओं जैसे-शहरी निकाय की सेवाओं की आपूर्ति, स्मार्ट खंभों के जरिये सैर आधारित ऑकड़ों का संग्रह, इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट टोस कचरा प्रबंधन और जलापूर्ति में जल्दी परिणाम देखने को मल सकते हैं ।

(टीम दृष्टि इनपुट)

मशिन स्मार्ट सटी में अब तक हुई प्रगति?

17 जनवरी, 2018 तक...

- 1,38,730 करोड़ रुपए की 2948 परियोजनाओं के कई चरणों का काम पूरा होने को है
- 2237 करोड़ रुपए की 189 परियोजनाएँ शीघ्र पूरी होने वाली हैं
- 36 शहरों में स्मार्ट सड़कों पर काम शुरू हो चुका है
- 30 शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है
- 37 शहरों में स्मार्ट वाटर प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं
- 44 शहरों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर काम चल रहा है
- 40 शहरों को सुंदर बनाने का काम भी चल रहा है

पश्चिमी देशों से अलग हैं भारतीय स्मार्ट सटी

देश में जनि स्मार्ट सटी का विकास करने की योजना है, वह यूरोपीय या अमेरिकी स्मार्ट सटी की अवधारणा से कुछ अलग है । भारत में स्मार्ट सटी परियोजना के तहत मौजूदा शहरी क्षेत्र को रहने योग्य बनाना है यानी कि शहरों की **रेट्रोफिटिंग** करना । इसका लक्ष्य शहर के एक हिस्से में आधुनिक सुख-सुविधाएँ वकिसति करना है, जिसके तहत शहर में कम-से-कम 500 एकड़ के हिस्से को नए रंगरूप में ढाला जा सकता है या फरि 25 एकड़ हिस्से को नए सिर से वकिसति किया जा सकता है या फरि बलिकूल नया शहर बसाया जा सकता है ।

(टीम दृष्टि इनपुट)

भारत में प्रस्तावित स्मार्ट सटी सुविधाएँ

- क्षेत्र आधारित घटनाक्रमों में मशिरति भू-उपयोग को बढ़ावा देना
- अनयोजित क्षेत्रों में भू-उपयोग को अधिक कुशल बनाना
- आवासन (Housing) के अवसरों का सभी के लिये वसितार करना

- पैदल और साइकलि चलने योग्य सड़कों का निर्माण
- स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना
- अंतःकरिया को बढ़ावा देने और सुरक्षा सुनिश्चित करना
- सड़क नेटवर्क को केवल वाहनों एवं सार्वजनिक परिवहन के लिये ही नहीं बल्कि पैदल चलने वालों और साइकलि चालकों के लिये भी बनाना
- पैदल या साइकलि से तय की जाने वाली दूरियों के लिये आवश्यक प्रशासनिक सेवाएँ प्रदान करना
- नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी करना
- शहरी क्षेत्रों में ताप-प्रभावों में कमी लाने और पारस्थितिकीय संतुलन बनाने के लिये खुले स्थानों, पार्क, खेल के मैदान, मनोरंजन के स्थानों का संरक्षण और विकास करना (पर्यावरण संरक्षण)
- परिवहन के विभिन्न विकल्पों को बढ़ावा देना
- पारगमन उन्मुख विकास, सार्वजनिक परिवहन और अंतमि गंतव्य स्थल पर परिवहन कनेक्टिविटी
- सेवाओं की कीमतों में कमी लाने और स्थानीय नकियों के कार्यालयों में जाए बिना सेवाएँ प्रदान करना
- इनके लिये जवाबदेही और पारदर्शिता लाने हेतु अधिकाधिक ऑनलाइन सेवाओं को उपलब्ध कराना
- शासन को सटिज़िन फ्रेंडली और कफियाती बनाना, विशेषकर मोबाइल उपयोग को
- लोगों के सुझाव लेने एवं कार्यस्थलों के कार्यकलापों की ऑनलाइन नगिरानी का उपयोग करने के लिये ई-समूहों का गठन करना
- स्मार्ट सटि के लिये चुने गए शहर में कम-से-कम एक ऐसा स्मार्ट फीचर होना चाहिये जो शहर के सभी नविसयियों की ज़िदगी से जुड़ा हो
- मुख्य आर्थिक कार्यकलापों के आधार पर शहर को पहचान प्रदान करना, जैसे-मुरादाबाद पीतल के लिये और लखनऊ चकिनकारी के लिये पहचाना जाता है
- अवसंरचना और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिये क्षेत्र आधारित विकास में उनके लिये स्मार्ट समाधान का उपयोग करना

मशिन स्मार्ट सटि की प्रमुख चुनौतियाँ

- राज्य और शहरी स्थानीय नकियों को स्मार्ट सटि के विकास में महत्त्वपूर्ण सहायक भूमिका नभानी होगी।
- इस स्तर पर स्मार्ट नेतृत्व और दृष्टि एवं नरिणायक कार्रवाई करने की क्षमता मशिन की सफलता का नरिधारण करने में महत्त्वपूर्ण कारक होगा।
- नीता नरिमाताओं, कार्यानवयन करने वालों एवं अन्य हतिधारकों द्वारा विभिन्न स्तरों पर रेट्रोफटिगि की अवधारणाओं को समझना, पुनर्विकास और गरीनफील्ड विकास हेतु क्षमता सहायता की जरूरत होगी।
- पूव योजना बनाने के दौर में ही समय और संसाधनों में प्रमुख नविश करना होगा।
- स्मार्ट सटि मशिन को सकरयि रूप से प्रशासन और सुधारों में भाग लेने वाले स्मार्ट लोगों की आवश्यकता है।
- नागरिक भागीदारी शासन में एक औपचारिक भागीदारी की तुलना में काफी अधिक है। स्मार्ट लोगों की भागीदारी को सूचना तकनीक के बढ़ते उपयोग, वशिष रूप से मोबाइल आधारित उपकरणों के माध्यम से एसपीवी द्वारा सकरयि कया जाएगा।

स्मार्ट सटि और नया शहरी एजेंडा

- जैसा हम बता चुके हैं कि 'स्मार्ट सटि' की संकल्पना, शहर-दर-शहर और देश-दर-देश भिन्न होती है, जो विकास के स्तर, परिवर्तन और सुधार की इच्छा, शहर के नविसयियों के संसाधनों और उनकी आकांक्षाओं पर नरिभर करती है। इस मशिन में शहरों के मार्गदर्शन करने के लिये कुछ पारभाषिक सीमाएँ अपेक्षित हैं।
- भारत में कसि भी शहर नविसी की कल्पना में, स्मार्ट शहर तस्वीर में ऐसी अवसंरचना एवं सेवाओं की अभीष्ट सूची होती है, जो उसकी आकांक्षा के स्तर को वर्णित करती है। स्मार्ट सटि अवधारणा, जहाँ नागरिकों की आकांक्षाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिये, शहरी योजनाकार को आदर्श तौर पर पूरे शहरी पारस्थितिकी तंत्र का विकास करना होता है, वही नया शहरी एजेंडा जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के लक्ष्यों को समाहित कयि हुए है।
- बेशक स्मार्ट सटि का वचिर ई-गवर्नेंस की अवधारणा को एक नए स्तर पर ले जाने का प्रयास है। पूरणतः स्मार्ट सटि हो जाने पर स्मार्ट सटि के नविसयियों की अधिकांश समस्याएँ स्वतः ही हल हो जाएंगी। स्मार्ट सटि बनने की आवश्यक शर्तों में ई-गवर्नेंस तो है ही, लेकिन यह एक धुरी मात्र है, जसि पर शेष सेवाएँ आधारित हैं। स्मार्ट सटि के महाअभियान में जनसाधारण को शामिल कयि बिना स्मार्ट सटि का सपना पूरा नहीं हो सकता। स्मार्ट सटि वस्तुतः एक ऐसा शहर होता है, जो सतत आर्थिक विकास व उच्च जीवन स्तर सुनिश्चित करता है तथा अर्थव्यवस्था, परिवहन, पर्यावरण, जीवन स्तर और सरकारी सेवाओं की सर्वोच्च श्रेष्ठता पर फोकस करता है। अतः स्मार्ट सटि मशिन और नए शहरी एजेंडे का मलिन भारत में शहरीकरण से उत्पन्न समस्याओं का समाधान बन सकता है।

(टीम दृष्टि इनपुट)

नविर्षः केंद्र सरकार ने जून 2015 में स्मार्ट सटि मशिन शुरू कयि था, जसिका लक्ष्य 100 शहरों को स्मार्ट सटि में बदलना है। इन शहरों में पर्याप्त जल और बजिली आपूर्ति, सफाई, सार्वजनिक यातायात, टोस कचरा प्रबंधन, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शक्ति, आधुनिक यातायात प्रबंधन व्यवस्था, सीसीटीवी नगिरानी और ई-प्रशासन के ज़रयि जीवन स्तर को बेहतर बनाया जाना है। अब केंद्र सरकार ने राज्यों से मशिन स्मार्ट सटि में उन स्मार्ट सटि परयोजनओं को शीघ्र लागू करने के लिये कहा है, जनिका नागरिकों के जीवन पर प्रत्यक्ष एवं परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ता है।

कसि भी देश में स्मार्ट सटि की अवधारणा वहाँ विकास के स्तर, परिवर्तन और सुधार की इच्छा, शहर के नविसयियों के संसाधनों और उनकी आकांक्षाओं पर नरिभर करती है। आज शहरीकरण और इससे उत्पन्न समस्याएँ देश के लिये एक बड़ा संकट बनकर सामने आए हैं और इसके लिये सभी संभावित उपाय कयि जा रहे हैं। ऐसे में स्मार्ट सटि जैसी पहल अत्यंत उपयोगी और सार्थक कही जा सकती है।

